समक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमारअजय कुमार मित्तल और जीएस संधावालिया,

सुश्री करुणा -अपीलकर्ता

बनाम

गवर्नमेन टी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ और अन्य- उत्तरदाता

2012 का LPA No.2142

मार्च 19,2013

पत्र पेटेंट, 1919 - CI.X - भारत विनियम की चिकित्सा परिषद - स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 - Regl.5(5)(ii) - अपीलकर्ता ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत एमई आरएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा, 2011 के लिए आवेदन किया -

उत्तीर्ण परीक्षा और 39.16% अंक प्राप्त किए - पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मेरिट सूची में चयनित - प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता को प्रवेश दिया - एमसीआई ने अपीलकर्ता को प्रवेश देने सहित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसने स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम, 1997 के अनुसार न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए ~ राज्यपालों के होर्ड ने स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमों के रेगक 5 (5) (ii) के विपरीत प्रवेश का फैसला किया - प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रवेश रद्द कर दिया चूंकि अपीलकर्ता ने सीईटी में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत यानी 40% हासिल नहीं किया है - रिट याचिका और एलपीए खारिज कर दिया गया - माना गया कि एमसीआई चिकित्सा से संबंधित पेशेवर संस्थानों को नियंत्रित करता है और इस प्रकार एमआर आरएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए विनियमन अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है - न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने में कोई विचलन या प्रस्थान नहीं किया जा सकता है - वचन पत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा उन्हें किसी भी लाभ के हकदार नहीं होगा क्योंकि एमसीआई विनियमन ने उन्हें अयोग्य बना दिया है एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार के लिए मेरिट सूची में नाम शामिल करना और रिट याचिका और एलपीए खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया, कि एमसीआई चिकित्सा से संबंधित पेशेवर संस्थानों को नियंत्रित करता है। अत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए भारतीय आयुवळ्ाना परिषद विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अपेक्षित है। संविधि और उसके अंतर्गत पारित विनियमों के अनुसार व्यावसायिक संस्थाओं से न्यूनतम मानकों को बनाए रखना अपेक्षित है। उन मानकों को प्राप्त करने में कोई विचलन या प्रस्थान नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, मेधावी छात्रों द्वारा संतुष्ट होने के लिए एक बहुत ही उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में केवल योग्यता ही उम्मीदवारों के चयन का

आधार होगी। चिकित्सा जैसी व्यावसायिक शिक्षा किसी भी उम्मीदवार को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगी जो एमसीआई विनियमों के विनियमन 4 के संदर्भ में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं करता है और साथ ही, पेशे में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, एमसीआई विनियमों के विनियमन 5 के तहत अनिवार्य रूप से सामान्य 1 इन ट्रान्स टेस्ट को भी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अर्हक परीक्षा अथवा सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत को कम करने वाले एमसीआई विनियम से भिन्न किसी विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी विवरणिका में कोई सांविधिक बल नहीं होगा। इस प्रकार, इसमें शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर भिन्न होने के कारण, अपीलकर्ता श्री कृष्ण के मामले (सुप्रा) में निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

आगे कहा गया कि समान रूप से, वचन पत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा उन्हें पूर्वोक्त सिद्धांत को लागू करके कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं बनाएगा क्योंकि एमसीआई विनियमों में निर्धारित सीईटी में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त नहीं करने से वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार करने के लिए मेरिट सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अयोग्य हो गए थे। इस पद्धति से, किसी भी विनियमन, नियम या क़ानून के तहत निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ताओं की ओर से कोई लाभ का आग्रह नहीं किया जा सकता है। मुद्दे नं. (क) और (ख) का तदनुसार उत्तर दिया गया है।

(पैरा 21)

आगे कहा गया कि हालांकि 20.12.2012 को अपील की सुनवाई करने वाली प्रस्ताव पीठ ने अपीलकर्ताओं को कक्षाओं में भाग लेने और परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी थी, जो विशेष रूप से इस शर्त के साथ थी कि यह कानून में कोई अधिकार या उनके पक्ष में इक्विटी नहीं बनाएगी, रिट याचिका में भी इसी तरह का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इक्विटी या कानून में किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। एमसीआई विनियमों के विपरीत अपनी विवरणिका प्रकाशित करने में कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई गलती या त्रुटि छात्र को प्रवेश के लिए किसी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करेगी जो कानून की अदालत में लागू करने में सक्षम होगा। साथ ही, छात्रों के लिए कानून के अनुसार गलत कर्ता के खिलाफ उपयुक्त नुकसान का दावा करने के लिए खुला होगा। इसके अलावा, एमसीआई भी मामले की जांच करेगी और अपीलकर्ताओं के करियर को प्रभावित करने वाली ऐसी त्रुटि के लिए आई एनएसटीआई टीयूटीसी/यू विविधता के खिलाफ उचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।

(पैरा 35)

अमन अरोड़ा, अपीलकर्ता के वकील।

विशाल सोढ़ी, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील।

दीपक सिब्बल, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए वकील।

अजय कुमार मित्तल, जे.

(एक) यह आदेश 2012 के एलपीए संख्या 2142, 2147 और 2165 वाली तीन अपीलों के एक समूह का निपटारा करेगा, क्योंकि पार्टियों के लिए विद्वान वकील के अनुसार, इसमें समान मुद्दे शामिल हैं। संक्षिप्तता के अनुसार, 2012 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2142 से निकाले जा रहे तथ्यों को आर्क किया जा रहा है।

(दो) इस अपील में, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 11.12.2012 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत 2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7928 को खारिज कर दिया गया था।

(तीन) संक्षेप में, वर्तमान अपील के अधिनिर्णय के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने अप्रैल, 2011 के महीने में अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा, अर्थात् 2011 की कॉमन एंट्रेंस लेस्ट (सीईटी) के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्ता ने 39.16% अंक हासिल करके उक्त सीईटी पास की और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में उसका चयन हुआ। इसके बाद, अपीलकर्ता ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतिवादी नंबर 1 से दूसरा प्रॉस्पेक्टस प्राप्त किया। प्रतिवादी नंबर 1 ने विभिन्न उम्मीदवारों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची तैयार की। एससी श्रेणी के लिए मेरिट सूची में, अपीलकर्ता सीरियल नंबर 7 पर था और कुल मिलाकर वह सीरियल नंबर 99 पर था। दूसरी मेरिट सूची के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता को 13.7.2011 (अनुलग्नक पी -4) की रसीद स्वीकार करके एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 18.7.2011 से अपनी कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया और हिट 25.4.2012 तक जारी रहा। अपीलकर्ता द्वारा कक्षाओं में भाग लेने के कई महीनों बाद, प्रतिवादी नंबर 1 वीआईडीसी आदेश दिनांक 25.4.2012 (अनुलग्नक पी -6) ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसने सीईटी में न्यूनतम प्रतिशत यानी 40% अंक हासिल नहीं किए थे। उक्त अन्य प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.4.2012 (अनुलग्नक पी-5) के आधार पर पारित किया गया था। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने 2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7928 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(चार) उक्त रिट याचिका को प्रतिवादियों ने अलग-अलग लिखित बयान दाखिल करके चुनौती दी थी। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में दलील दी कि वह केवल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों को प्रवेश दे सकता है और एमसीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की अनदेखी या अनदेखी करने की कोई शक्ति नहीं है। इसने आगे दलील दी कि अपीलकर्ता के प्रवेश को रद्द करने का आदेश एमसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार था। प्रतिवादी संख्या 3-एमसीआई ने अपने उत्तर में दलील दी कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति के छात्र के तहत सीईटी परीक्षा में उपस्थित हुआ था और उसने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 39.16% अंक प्राप्त किए थे, जबकि एमसीआई विनियमों के अनुसार, उक्त तीन विषयों में सीईटी में अंकों का न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए 40% है। आगे यह दलील दी गई कि एक बार के लिए प्रवेश
शैक्षिक सत्र 2011-12 समाप्त हो चुका था, एमसीआई ने सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थाओं को दिनांक 29-09-2011 को परिपत्र जारी किया था कि वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में उनके द्वारा किए गए दाखिलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सभी दाखिले सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए मेरिट के आधार पर किए गए हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ने तदनुसार एमसीआई को दिनांक 25.10.2011 को अपना संचार भेजा, जिसने दिनांक 4.1.2012 के पत्र में स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 पर विनियमों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने के बावजूद अपीलकर्ता के टायर प्रवेश सहित कुछ मुद्दों पर क्लेरी फिकेशन की मांग की। तत्पश्चात्, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने विधिक राय ली और मामले को शासी मंडल के समक्ष रखा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैसला किया कि अपीलकर्ता का प्रवेश स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमों के विनियमन 5 (5) (ii) के विपरीत था और आदेश दिया कि अपीलकर्ता को पाठ्यक्रम से छुट्टी दे दी जाए। उक्त आदेश की सूचना प्रतिवादी नंबर 1 को 18.4.2012 को दी गई थी। प्रतिवादी नंबर 1 ने तदनुसार अपीलकर्ता को 25.4.2012 को एमबीबीएस के पाठ्यक्रम से छुट्टी दे दी।

(पाँच) विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 11122012 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान पत्र पेटेंट अपील।

(छः) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अमन अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस (अनुलग्नक पी -1) के आधार पर, अपीलकर्ता पात्र थी क्योंकि उसने निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा किया था और योग्यता मानदंडों की गणना की थी: -

(सात) यूटी पूल के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है: –

परीक्षण उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुला होगा जो

(अ) 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु प्राप्त करें

(आ) मैंने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित स्कूलों/कॉलेजों से उक्त स्कूलों/कॉलों के नियमित छात्रों के रूप में 10 + 2 (12 वीं कक्षा) की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। उसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषय में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए, और कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए पहले प्रयास में 101 2 स्तर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की। प्रवेश सीईटी 1 में मेरिट के आधार पर होगा, अनुसूचित जाति के सदस्यों की आसानी में, 10% से अधिक अंकों में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी,

नहीं तो

(इ) आर्क में दिखाई देने के कारण! (ख) मार्च, 2011 में परीक्षा सं 2 (12वीं कक्षा) के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, किन्तु जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, परीक्षा में ऐसे अभ्यथयों का प्रवेश अनंतिम होगा। यदि वे निर्धारित अंकों के प्रतिशत को सुरक्षित करने वाली क्वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं तो यह रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों का उक्त पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश के संबंध में कोई दावा नहीं होगा। अन्य पात्रता शर्तें उपर्युक्त

मेरिट लिस्ट

(अ) विश्वविद्यालय विषयों के निम्नलिखित संयोजनों के लिए उम्मीदवारों की सीईटी मेरिट सूची प्रकाशित करेगा:

एक. कानूनी और GcncralAwarcncss

दो. पर्यटन और होटल प्रबंधन

तीन. भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, (मेडिकल मेरिट)

चार. भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित (पीसीएम मेरिट)

पाँच. भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी

छः. भौतिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान

सात. केवल गणित।

(आ) एक उम्मीदवार को न्यूनतम 15% (कट ऑयल) कुल ओ (समग्र रूप से ली गई परीक्षा में अधिकतम अंक) की प्राप्ति के आधार पर एक विशेष योग्यता सूची में शामिल किया जाएगा। केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों की

आसानी में, यह आवश्यकता सीईटी परीक्षा में अधिकतम अंकों के 10% (कट ऑयल) कुल की न्यूनतम प्राप्ति होगी, जिसे समग्र रूप से लिया जाएगा।

(इ) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एक साथ ब्रैकेट किया जाएगा। उनकी इंटर एससी मेरिट संबंधित प्राधिकारी द्वारा इंटर्नक्रिप्शन/काउंसलिंग के समय निर्धारित की जाएगी, जैसा कि प्रवेश प्रक्रिया में बताया गया है।

(ई) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मेरिट सूचियों के आधार पर किया जाएगा।

(सात) विद्वान वकील के अनुसार, कैस्कोफगसीएनसीआरएलकैटगरी में विवरणिका में दिए गए सीएल टीपी में मंगल का न्यूनतम प्रतिशत 15% था जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की आसानी में यह 10% था। श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (I) में 1 आयन टाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया था कि प्रॉस्पेक्टस में कानून का एक बल है और उस आधार पर दिए गए प्रवेश को बाद में रद्द नहीं किया जा सकता था। एस्टोपेल के सिद्धांत को यह तर्क देने के लिए लागू किया गया था कि एमसीआई को सतर्क रहना चाहिए था और छात्रों की ओर से कोई गलती नहीं थी। अपीलकर्ता प्रॉस्पेक्टस के साथ-साथ एमसीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से पात्र थे और सीईटी केवल चयन के लिए था।

(आठ) एमसीआई विनियमों के विनियम 4 और 5 का संदर्भ दिया गया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि विनियम 4 और 5(2) के बीच अंतर मौजूद है। राजन पुरोहित और अन्य बनाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ (2) मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया था।

(नौ) इक्विटी का दावा इस दलील पर किया गया था कि मोनिका रांका अनिल अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य (3), दीपा थॉमस और अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य (4) और राजेंद्र प्रसाद माथुर बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय और अन्य (5) पर भरोसा करके एक साल का कोर्स पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि दयानंद मेडिकल कॉलेज में अवलोकन केवल आज्ञाकारी था। कोर्ट का ध्यान उस स्थिति की ओर भी आकर्षित किया गया जहां एनआर 1 छात्रों को सीईटी परीक्षा देने से छूट दी गई थी।

(दस) श्री 1 लार्श अग्रवाल और श्री बीबी बग्गा, अन्य अपीलों में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भी एमसीआई विनियमों के विनियम 4 और 5 के संदर्भ में समर्थन प्राप्त करने की मांग की। एफओ 11 के फैसले से भी समर्थन जुटाया गया

(अ) मैसूर के एक विश्वविद्यालय (6) ।

(आ) पीसी चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य (7).

(ग्यारह) दूसरी ओर, उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, 2012 -8 की एलपीए संख्या 2142- श्री दीपक सिब्बल ने प्रस्तुत किया (सुश्री करुणा और विक्रम सिंह ने सीईटी परीक्षा में क्रमशः 39.16% और 38.61% प्राप्त किया था, जबकि न्यूनतम आवश्यकता 40% थी, जबकि सुश्री सोनिया शन्ना ने सीईटी परीक्षा में 24.67% प्राप्त किया था, जबकि एम बीबीएस कोर्स के लिए मेरिट सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक 45% था।

(बारह) मुस्कराते हुए वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को आसानी से प्रवेश की अनुमति दी जाती है, यह कानून के उल्लंघन में होगा जिसकी अनुमति नहीं है। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि एमसीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन किया जाना आवश्यक था और पंजाब बनाम दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और अन्य (8) के एटो/ई में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था:

(तेरह) स्पष्ट है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के अलावा अन्य विषयों में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे और अन्य विषयों के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है। प्रथम न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में यह कहा गया है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी जैसे बुनियादी विषयों के लिए अंकों का प्रतिशत 40% से कम कर दिया गया है क्योंकि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार इन विषयों का चयन नहीं करते हैं और इस तरह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभागों में स्नातकोत्तर स्कैट्स खाली पड़े रहते हैं और इस प्रकार इन विभागों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाती है। इसके अलावा, प्रवेश पूर्व में 50% अंकों की शर्त को घटाकर 40% कर दिया गया क्योंकि 80%

पीसीएमएस के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश सीटें खाली रह गई क्योंकि उनमें से अधिकांश पीजीईटी में 50% अंक इस तथ्य के कारण सुरक्षित नहीं कर सके कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सहायता नहीं मिलती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित की जाती है जो पहले ही कम से कम 50% अंक हासिल करके एमबीबीएस

परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और इसलिए, जिन उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त नहीं किए थे, उन्हें एमबीबीएस में भरा जाना घोषित नहीं किया जा सकता है। 50% से कम अंकों को कम करने का दोहरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना और संवैधानिक दायित्व को पूरा करना है। हमें डर है कि इस संबंध में पंजाब राज्य के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप तर्क को विफल कर दिया जाता है। तर्क दिया गया है कि पात्र उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाना है और इस संबंध में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। जब ऐसी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है तो भारतीय आयुवज्ञान परिषद द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के अनुसार एक मानक निर्धारित करते हुए एक नुस्खा दिया गया है और जिसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया जा सकता है जैसा कि डा प्रीति श्रीवास्तव मामला, डा नारायण शर्मा बनाम डा पंकज कुमार लहकर और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कर्णाटक राज्य सहित निर्णयों की श्रृंखला में किया गया है। इसलिए, विश्वविद्यालय या सरकार भारतीय आयुवज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित अंक से कम अंक निर्धारित करके उस मानक को कम नहीं कर सकती है। यदि उन्हें कोई कठिनाई होती थी तो उन्हें इस संबंध में उचित मानक तय करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद से संपर्क करना चाहिए था। राज्य सरकार भारतीय आयुवज्ञान परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मानक को कम करने वाली योजना एकतरफा नहीं बना सकी, जिसे इस न्यायालय द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन में मानकों को निर्धारित करने की शक्ति का भंडार होने के लिए बार-बार कहा गया है, निस्संदेह, परिषद के गठन वाले अधिनियम में यथापरिकल्पित केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन।

(अठ्ठारह) अब हमें यह देखना है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने के लिए दिए गए नुस्खे के अनुरूप है और उस आधार पर उनके रोस्टर संचालित करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं और यदि 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा,

इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि किसी छात्र ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो केवल प्रवेश रद्द करना होगा और आरक्षित श्रेणी के किसी अन्य अभ्यर्थी का चयन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। फिर उसे जेनेरा से चुना जाना चाहिए! कोटि।

(उन्नीस) इसलिए, हम पाते हैं कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार करने के लिए और बुनियादी विषयों के संबंध में कोई न्यूनतम

मानक निर्धारित करने के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अंकों को कम करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया नुस्खा स्पष्ट रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों का उल्लंघन है और अधिसूचना के उस भाग को नजरअंदाज करना होगा। यदि ऐसा किया जाता है और यदि भारतीय आयुवज्ञान परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों को पूर्णत लागू किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को यथा संकेतित, सुप्रा समुचित कार्य करना होगा और उसे लागू करना होगा।

(तेरह) एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (9), सीबीएसई और अन्य बनाम पी सुनील कुमार और अन्य (10) और श्री मोरवी सार्वजनिक केलावनी मंडल संचलित एमएसकेएम बीएड कॉलेज बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और अन्य (11) में रिपोर्ट किए गए निर्णयों के आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए इक्विटी के आधार का कड़ा विरोध किया गया था। /टी एचएमदाबाद नगर निगम बनाम वीरेंद्र कुमार जय विरोधी भाई पटेल (12) के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले के पैरा 5 से भी समर्थन लिया गया था , जो इस प्रकार है: -

(चौदह)ट्रिब्यूनल द्वारा निगम को अपनी तपस्या सेवा में प्रतिवादी को अवशोषित करने के लिए निर्देश जारी करने में दिया गया दूसरा तर्क यह है कि प्रतिवादी के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संभवतः प्रतिवादी सत्तर के दशक की शुरुआत से निगम के क्लिनिक का दौरा कर रहा है, इस पर विचार किया जाना बाकी है। जैसा कि पहले देखा गया है, भर्ती

(नौ) (1986) 2 एससीसी 667

(दस) (1998) 5 एससीसी 377

(ग्यारह) (2012) 2 एससीसी 16

(बारह) 1997(4)आरएसजे19

निगम द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक में डाक्टरों की संख्या सांविधिक नियमों के अनुसार बनाई जाती है और किसी अन्य विधि से नहीं। नियमों के तहत पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्तियों का विज्ञापन किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद निगम के क्लिनिक में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन किया जाता है। उम्मीदवारों के चयन के बाद ही उन्हें सेवा में लिया जाता है। यह भी पहले देखा गया है कि प्रतिवादी चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुआ लेकिन उसका चयन नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी नियुक्ति के मामले में सहानुभूति या समानता के लिए कोई जगह नहीं है, विशेष रूप से जहां सेवा में भर्ती सांविधिक नियमों द्वारा शासित होती है। (च) यदि टीएलआईसी

अधिकरण द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो सांविधिक भर्ती नियम निरर्थक हो जाएंगे और विभाग भर्ती नियमों में उपबंधित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी व्यक्ति का पक्ष ले सकता है अथवा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिससे भाई-भतीजावाद और मनमानापन पनपेगा। एक बार जब सांविधिक नियमों के सामने इक्विटी पर विचार स्वीकार कर लिया जाता है तो पात्र और योग्य व्यक्ति पीड़ित होंगे क्योंकि उन्हें नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए कोई कैश नहीं मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि योग्यता में कम व्यक्तियों को केवल समानता और करुणा के आधार पर नियुक्ति के मामले में वरीयता मिलेगी। इसलिए केवल समानता को समायोजित करने के लिए कानून की बाहों को मोड़ना सुरक्षित नहीं है। इसलिए, हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया तर्क कि सहानुभूति निगम की सेवा में प्रतिवादी के अवशोषण की मांग करती है, कानून की त्रुटि से ग्रस्त है।

(चौदह)पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, इन अपीलों में विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठते हैं: -

(अ) क्या भारतीय आयुवळ्ाना परिषद विनियम अभिभावी होंगे और विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी विवरणिका पर वरीयता देंगे?

(आ) क्या पात्रता मानदंड की आवश्यकता प्रवेश के लिए पर्याप्त होगी और सामान्य प्रवेश परीक्षा की शर्त को पूरा न करने से अपीलकर्ता अभी भी वचन पत्र के सिद्धांत के आधार पर अपने प्रवेश को बनाए रखने का हकदार होगा?

(इ) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता अपने पक्ष में इक्विटी के दावे के हकदार हैं?

(15) पहले और दूसरे मुद्दे को एक साथ उठाते हुए, क्योंकि वे एक-दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एमसीआई विनियमों के विनियम 4 और 5 का उल्लेख करना उचित होगा। भारतीय आयुवळ्ाना परिषद विनियम के विनियम 4 में चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्रता मानदंड का प्रावधान है जबकि विनियम 5 का संबंध अभ्यथयों की योग्यता के आधार पर मेडिकल कालेजों में छात्रों के चयन से है। यह इस प्रकार पढ़ा

"4. मेडिकल कोर्स में प्रवेश- पात्रता मानदंड: किसी भी उम्मीदवार को पहले बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) कोर्स के मेडिकल पाठ्यक्रम में भर्ती होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(एक) वह एम बीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी करेगा;

(दो) उसने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है: –

(अ) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो 12 वर्ष की अध्ययन अवधि के बाद 10+2 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य है, अंतिम दो वर्षों का अध्ययन जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान और गणित या 10+24-3 की शुरुआत के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित अंग्रेजी के लिए कोर पाठ्यक्रम से कम नहीं स्तर पर अंग्रेजी के लिए कोई अन्य वैकल्पिक विषय शामिल हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुशंसित शैक्षिक संरचना; नोट: जहां पाठ्यक्रम सामग्री राष्ट्रीय समिति की 10 + 2 शिक्षा संरचना के लिए निर्धारित नहीं है, उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से पहले एक वर्ष की पीआरसी-पेशेवर प्रशिक्षण की अवधि से गुजरना होगा;

नहीं तो

(आ) बोर्ड या भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय के विज्ञान में इंटरमीडिएट परीक्षा जिसमें इन विषयों में एक व्यावहारिक परीक्षा शामिल होगी और अंग्रेजी भी अनिवार्य विषय के रूप में;

नहीं तो

(इ) 'हाय पीआरसी-प्रोफेसर/प्री-एमसीडिकल परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, या तो हायर स्कोंडे पास करने के बाद

स्कूल परीक्षा, या पूर्व-विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा। प्री-मेडिकल परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक व्यावहारिक परीक्षा और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी भी शामिल होगी;

नहीं तो

(ई) तीन विषयों में व्यावहारिक परीक्षा सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तीन साल की डिग्री कोर्स के टायर प्रथम वर्ष बशर्ते परीक्षा एक "विश्वविद्यालय परीक्षा" हो और उम्मीदवार ने अंग्रेजी के साथ 1 सीएच -2 उत्तीर्ण किया हो एक कोर कोर्स से कम नहीं;

नहीं तो

(उ) B.Sc. किसी भारतीय विश्वविद्यालय की परीक्षा, बशर्ते कि उसने निम्नलिखित विषयों भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान (वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी) में से कम से कम दो विषयों के साथ B.Sc परीक्षा उत्तीर्ण की हो और आगे उसने निम्नलिखित विषयों के साथ पहले की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो - भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी।

नहीं तो

(ऐ) कोई अन्य परीक्षा, जो कार्यक्षेत्र और मानक में भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के समकक्ष पाई जाती है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जिसमें इन विषयों में से प्रत्येक और अंग्रेजी में व्यावहारिक परीक्षा शामिल है। नोट:
प्री-मेडिकल कोर्स या तो मेडिकल कॉलेज या साइंस कॉलेज में आयोजित किया जा सकता है।
एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गणित में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10+2 पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद एकीकृत पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

5. छात्रों का चयन: मेडिकल कॉलेज में छात्रों का चयन पूरी तरह से उम्मीदवार की योग्यता पर आधारित होगा और योग्यता के निर्धारण के लिए, निम्नलिखित मानदंडों को पूरे देश में समान रूप से अपनाया जाएगा;

(एक) जिन राज्यों में केवल एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्वविद्यालय बोर्ड/परीक्षा निकाय है, वहां ऐसी अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जा सकता है;

(दो) उन राज्यों में, जहां अर्हक परीक्षा आयोजित करने वाले एक से अधिक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय हैं (या जहां एक प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं) एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अर्हक परीक्षा में मानकों में भिन्नता हो सके;

(तीन) जहां एक राज्य में एक से अधिक कॉलेज हैं और केवल एक विश्वविद्यालय / बोर्ड योग्यता परीक्षा आयोजित करता है, तो सभी कॉलेजों के लिए एक संयुक्त चयन बोर्ड का गठन किया जाता है;

(चार) भारतीय स्वरूप की संस्थाओं के मामलों में एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा नितांत आवश्यक है;

(पाँच) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी: –

(१) योग्यता के आधार पर खंड (1) के तहत योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम 50% प्राप्त करना चाहिए विनियमन 4 के खंड (2) में उल्लिखित योग्यता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक साथ लिया गया अंक। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में योग्यता परीक्षा में एक साथ लिए गए अंक उपरोक्त के अनुसार 50% के बजाय 40% हैं;

(२) इस विनियम के खंड (2) से (4) के तहत प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में, एक उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम 4 के खंड (2) में उल्लिखित योग्यता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक साथ लिए गए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए और इसके अलावा

(ग) ऐसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के परिणामस्वरूप प्रतियोगी परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम 50% अंक प्राप्त करके तैयार की गई मेरिट सूची में शामिल हुए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अर्हक परीक्षा और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में एक साथ लिए गए अंक ऊपर बताए अनुसार 50% के बजाय 40% हैं।

परन्तु कोई अभ्यर्थी जो अर्हक परीक्षा में उपस्थित हुआ है जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, उसे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा देने की अनंतिम रूप से अनुमति दी जा सकती है और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन होने की स्थिति में, उसे उस पाठ्यक्रम में तब तक दाखिला नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह विनियम 4 के अंतर्गत पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर लेता है।

(सोलह) भारतीय आयुवळ्ाना परिषद विनियम के विनियम 4 में चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार किसी भी उम्मीदवार को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि; (ए) उसने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और (बी) उसने उसमें निर्धारित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(सत्रह) भारतीय आयुवळ्ाना परिषद विनियम का विनियम 5 अभ्यथयों की योग्यता के आधार पर मेडिकल कालेजों में विद्याथयों के चयन से संबंधित है। योग्यता के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिन्हें पूरे देश में समान रूप से अपनाया जाना अपेक्षित है। विनियम 5 के खंड (2) और 5(ii), इन अपीलों के निर्णय के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं। विनियम 5 के खंड (2) के अंतर्गत जिन राज्यों में अर्हक परीक्षा आयोजित करने वाले एक से अधिक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय हैं, वहां एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि एक समान मूल्यांकन प्राप्त किया जा सके क्योंकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अर्हक परीक्षा में मानकों में अंतर हो सकता है। विनियम 5 का खंड (5)(ii), उन मामलों से संबंधित है जहां एमसीआई विनियमों के विनियमन 5 के खंड (4) के तहत प्रतियोगी प्रवेश

परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाना है। इसके अनुसार, एक उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों को व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करना आवश्यक है और योग्यता में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक साथ 50% अंक प्राप्त करने चाहिए इन विनियमों के खंड 4(2) के अंतर्गत यथापेक्षित जांच। इसके अतिरिक्त, उनके नाम प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में दिखाई देने चाहिए, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंक 50% से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में 10% की छूट प्रदान की गई है। दूसरे शब्दों में, जहां एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उसे अर्हक परीक्षा और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विषयों में एक साथ लिए गए 50% अंकों के बजाय 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(18) डॉ. (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (जे 3) की एक समिति में उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा के लिए मानकों को निर्धारित करने और एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित संस्थाओं में मानकों को निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह निर्धारित किया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने वाले एमसीआई के विनियमों का अनुपालन किया जाना होगा। इसे इस प्रकार देखा गया: -

"55. हम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 20 पर लगाई गई इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। धारा 20 (1) (पहले निर्धारित) तीन भागों में है। पहले भाग में प्रावधान है कि परिषद विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानकों को निर्धारित कर सकती है। सदस्यता के दूसरे भाग (1) में कहा गया है कि परिषद विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए यूनिफोन मानकों को पूरा करने के मामले में सलाह दे सकती है। उपधारा (1) का अंतिम भाग केन्द्र सरकार को परिषद के सदस्यों में से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति गठित करने में समर्थ बनाता है। उप-धारा (1) का पहला भाग परिषद को विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसलिए, विश्वविद्यालयों को चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों से निर्देशित होना चाहिए और तदनुसार अपने कार्यक्रमों को आकार देना चाहिए। भारतीय आयुवज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की योजना विश्वविद्यालयों को भारतीय आयुवज्ञान परिषद द्वारा

निर्धारित मानकों का अनुपालन करने अथवा न करने का विकल्प प्रदान नहीं करती है। उदाहरण के लिए, द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यता

(13) (1999) 7 एससीसी 120

किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान को भारतीय आयुवज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जब तक अर्हताओं को इतनी मान्यता नहीं दी जाती, अर्हता प्राप्त करने वाले छात्र पै्रक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसी मान्यता प्रदान करने से पूर्व, धारा 16 के अंतर्गत आयुवज्ञान परिषद को अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी मांगने की शक्ति दी गई है। विश्वविद्यालय परिषद द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा समिति धारा 17 के अंतर्गत किसी भी चिकित्सा संस्थान, कॉलेज, अस्पताल या अन्य संस्थान, जहां चिकित्सा शिक्षा दी जाती है, का निरीक्षण करने के लिए चिकित्सा निरीक्षकों को नियुक्त करने या किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा योग्यता की सिफारिश करने से पहले किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए भी हकदार है। धारा 19 के तहत, यदि समिति की कोई रिपोर्ट असंतोषजनक है तो चिकित्सा परिषद धारा 19 में दिए गए तरीके से संबंधित किसी चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय की चिकित्सा योग्यता को दी गई मान्यता वापस ले सकती है। धारा 19 ए परिषद को विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता के अलावा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है, जबकि धारा 20 परिषद को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने की शक्ति देती है। यदि विश्वविद्यालयों की डिग्री या डिप्लोमा को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत मान्यता दी जाती है तो उन्हें आवश्यक रूप से धारा 20 (1) के तहत निर्धारित मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इसलिए, डब्ल्यूसी, अजय कुमार बनाम भारत संघ में दिए गए निष्कर्ष से असहमत हैं और इसे खारिज करते हैं। बिहार राज्य ने इस आशय के लिए कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानक केवल निर्देशिका हैं और विश्वविद्यालय इस प्रकार निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

(उन्नीस) इसी तरह का विचार ^ मध्य प्रदेश और अन्य बनाम गोपाल डी. तीर्थानी और अन्य (14) और हरीश वर्मा बनाम अजय श्रीवास्तव और अन्य (15) में व्यक्त किया गया था।

(बीस) एमसीआई चिकित्सा से संबंधित पेशेवर संस्थानों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए एमसीआई विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। के संदर्भ में क़ानून और पारित नियम thcreupd.e^.fhe.professio.n^l institutions.arc न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन मानकों को प्राप्त करने में कोई विचलन या प्रस्थान नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, मेधावी छात्रों द्वारा संतुष्ट होने के लिए एक बहुत ही उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में, केवल योग्यता ही उम्मीदवारों के चयन का आधार होना चाहिए। चिकित्सा जैसी व्यावसायिक शिक्षा किसी ऐसे उम्मीदवार को दाखिला नहीं दे पाएगी जो भारतीय आयुवळ्ाना परिषद विनियमों के विनियम 4 के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं करता है और साथ ही, व्यवसाय में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय आयुवळ्ाना परिषद के विनियम 5 के अंतर्गत यथा अधिदेशित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अपेक्षित है। किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा एमसीआई विनियम के साथ भिन्नता पर जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में अर्हक परीक्षा या सामान्य प्रवेश टीसीएसटी के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत को कम करने का कोई सांविधिक बल नहीं होगा। इस प्रकार, इसमें शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर भिन्न होने के कारण, अपीलकर्ता श्री कृष्ण के मामले (सुप्रा) में निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(इक्कीस) समान रूप से, वचन पत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा उन्हें पूर्वोक्त सिद्धांत को लागू करके कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा क्योंकि मुख्य रूप से एमसीआई विनियमों में निर्धारित सीईटी में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त नहीं करने से उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार के लिए मेरिट सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अयोग्य बना दिया गया था। इस पद्धति से, किसी भी विनियमन, नियम या क़ानून के तहत निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ताओं की ओर से कोई लाभ का आग्रह नहीं किया जा सकता है। मुद्दे नं. (क) और (ख) का तदनुसार उत्तर दिया गया है।

(बाईस) तीसरे अंक पर ध्यान देते हुए, यह देखा जा सकता है कि उत्कृष्टता के मानक को संरक्षित और बनाए रखा जाना चाहिए। उच्च स्तर पर, विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों/संस्थानों में, यह आम सहमति की आवश्यकता होगी कि औसत दर्जे और गुणवत्ता को नष्ट करने से परहेज करते हुए सर्वश्रेष्ठ को प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से व्यावसायिक संस्थानों में, सीईटी उत्तीर्ण करना और न्यूनतम अंक निर्धारित करना पेशे में गुणवत्ता, उत्कृष्टता

और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता है। यह न्यूनतम मानकों और योग्यताओं को निर्धारित करके प्राप्त किया जा सकता है जो पास होनी चाहिए
उम्मीदवारों द्वारा। विशेष रूप से चिकित्सा व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, एक बहुत ही उच्च क्षमता की मांग की जाती है जिसे केवल मेधावी छात्रों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अच्छे चिकित्सक तैयार करने के लिए, केवल योग्यता ही उम्मीदवारों के चयन का आधार होनी चाहिए। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (16) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता पहला मानदंड होगा। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट किया गया है कि योग्यता और उत्कृष्टता प्रो फेशन अल अध्ययनों के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं। आरए में। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (जे 7) के मामले में यह भी नोट किया है कि यद्यपि योग्यता और उत्कृष्टता गैर-व्यावसायिक शिक्षा के लिए अभिशाप नहीं है, फिर भी उस स्तर पर और शिक्षा की प्रकृति के कारण जो अधिक सामान्य है, उसमें योग्यता और उत्कृष्टता की आवश्यकता उस स्तर की नहीं है जैसी कि पेशेवर शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षित है। आगे यह भी दर्ज किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा योग्यता के मानदंड पर और सभी पात्र छात्रों को एक समान आधार पर गैर-एक्सप्लोइलेटिव टेन्स पर सुलभ कराई जानी चाहिए।
(तेईस) एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (18) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार देखा: -
"हम अपने आदेश से विश्वविद्यालय को उस क़ानून की अवज्ञा करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं जिसके लिए वह अपने अस्तित्व और स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों का श्रेय देता है। हम कानून की अवहेलना करने के लिए अदालत के निर्देश से ज्यादा विनाशकारी कानून के शासन की कल्पना नहीं कर सकते।
(चौबीस) इस निर्णय पर भरोसा करते हुए, सीबीएसई और एक अन्य बनाम पी सुनील कुमार और अन्य (19) में, पेनिट छात्रों के स्वामित्व से संबंधित मुद्दे को सहानुभूति के आधार पर उपस्थित होने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था: -
(पच्चीस) "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस संस्थान में इन छात्रों ने अपनी पढ़ाई की थी, उसे अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई संबद्धता नहीं मिली है, जो इन संस्थानों में अपीलकर्ता है

दो हजार पाँच.) 6 एससीसी 537

एक हजार नौ सौ छियासी.) 2 एससीसी 667

एक हजार नौ सौ अठ्ठानवे.) 5 एससीसी 377

अपील। बोर्ड के उपनियमों के अंतर्गत बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के केवल नियमित छात्र ही माध्यमिक स्कूल परीक्षा और बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परीक्षा में बैठने के हकदार हैं। चूंकि जिन संस्थानों में प्रतिवादी - छात्रों ने अपनी पढ़ाई पर मुकदमा चलाया है, वे बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन छात्रों को अदालत के अंतरिम निर्देश के अनुसरण में परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, जो बोर्ड के नियमों और विनियमों का उल्लंघन है, विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह है: क्या न्यायालय द्वारा इन आक्षेपित निदेशों को जारी करना न्यायोचित था? यह सवाल अब रेस इंटीग्रा नहीं रहता है। 'इलिस कोर्ट ने कई मामलों में छात्रों को बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने की प्रथा की निंदा की और अंततः मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे नियमित किया। की आसानी में ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी वी। आन्ध्र प्रदेश सरकार और एक अन्य मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों और विश्वविद्यालय के विनियमों के स्पष्ट उल्लंघन में मेडिकल कॉलेज में दाखिल किए गए छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय को निदेश जारी करना न्यायालय न्यायोचित नहीं होगा। यह भी देखा गया कि अदालत अपने आदेश द्वारा विश्वविद्यालय को उस क़ानून की अवज्ञा करने का निर्देश नहीं दे सकती है जिसके लिए वह अपने अस्तित्व का बकाया है और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों को समाप्त कर सकता है क्योंकि यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा। टी.एन.वी. सेंट जोसेफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि गैर-न्यायिक शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को प्रवेश देने और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के संबंध में अनुचित तरीके से देखा गया है और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र जो कानूनी रूप से सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और प्रथम न्यायालय ने ऐसे छात्रों को अनुमति देने में त्रुटि की है सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए। इन सभी सुगमताओं पर महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव राउंडेबल और अन्य के मामले में न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुन विचार किया गया और यह माना गया कि गैर-मान्यता प्राप्त और अनधिकृत शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा में बैठने और मान्यता प्राप्त में समायोजित करने के लिए दायर की जा रही रिट याचिका पर अनुमति नहीं दी जा सकती थी

संस्थानों। 'इली कोर्ट ने अंततः उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश को रद्द कर दिया। एक और सहजता में। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुरू नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कुमार बंसल और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिनांक 10-11-2008 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया था कि इस न्यायालय की अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया है जिसमें छात्रों को एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना भी इन्टर्नशिप पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 403 पैरा 7) "हमें डर है कि इस तरह के वार्ताकार उपचारों का प्रशासन, सहानुभूति द्वारा निर्देशित काफी ओ हेन पूरी तरह से गलत है, किसी की कोई सेवा नहीं करता है। अकादमिक मामलों में हमारे सामने आने वाले आदेशों की गड़गड़ाहट को दूर करते हुए, हम पाते हैं कि ढीली, बीमार सहानुभूति निजी परोपकार में जाने की आलोचना के लिए न्यायिक विवेक को न्यायसंगत न्याय के रूप में प्रस्तुत करती है। 'फिस अकादमिक अनुशासन के विध्वंसक हैं, या जो कुछ भी बचा है, वह अकादमिक लीग एफसी में गंभीर गतिरोध पैदा करता है। कैंडी तिथियों की पात्रता की परवाह किए बिना प्रवेश का आदेश नहीं दिया जा सकता है^ निर्णय • इंटरलोक्यूटरी चरण में ध्यान में रखे जाने के लिए प्रासंगिक मामलों पर निर्णय को स्थगित या बाद में तय नहीं किया जा सकता है जब अंतरिम आदेश से ही गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया कानूनी स्थिति के सटीक मूल्यांकन द्वारा उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति से प्रथम दृष्टया न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसे आदेशों को खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालतों को अकादमिक अधिकारियों को अपने कार्यों को अपने हाथों में लेकर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।

पच्चीस. इसी प्रकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम केयू के मामले में व्यक्त किया गया था। शीना पीठ अंबरन व अन्य (20)।

छब्बीस.) गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कुमार बंसल (21) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शैक्षणिक मामलों से संबंधित निम्नानुसार नोट किया

"हमें डर है कि इस तरह के वार्ताकार उपचारों का प्रशासन, सहानुभूति द्वारा निर्देशित अक्सर पूरी तरह से गलत होता है, किसी के लिए कोई सेवा नहीं करता है। अकादमिक मामलों में हमारे सामने आने वाले आदेशों की श्रृंखला से, हम पाते हैं कि ढीली, अकल्पनीय सहानुभूति न्यायिक को उजागर करने वाले वार्ताकार न्याय के रूप में मुखौटा लगाए हुए है

निजी परोपकार में डीसीजीसी की आलोचना के लिए विवेक। यह अकादमिक अनुशासन का विध्वंसक है, या जो कुछ भी बचा है, वह अकादमिक जीवन में गंभीर गतिरोध पैदा करता है। उम्मीदवारों की पात्रता की परवाह किए बिना प्रवेश का आदेश नहीं दिया जा सकता है। वार्ताकार चरण में ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक मामलों पर निर्णयों को स्थगित नहीं किया जा सकता है या बाद में निर्णय नहीं लिया जा सकता है जब अंतरिम आदेश से ही गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। वर्तमान सहजता में, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित था, यहां तक कि प्रथम दृष्टया कानूनी स्थिति के सटीक मूल्यांकन के बजाय। ऐसे आदेशों को खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालतों को अकादमिक अधिकारियों को उनके कार्यों को अपने हाथों में लेने के लिए शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।

सत्ताईस. () सुनील उरांव (नाबालिग) के मामले में गार्जियन और अन्य बनाम सीबीएसई और अन्य (22) के माध्यम से, यह निम्नानुसार दर्ज किया गया था: -

अठ्ठाईस. . अब, हम इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में तय किए गए कानून का उल्लेख करेंगे कि वर्तमान मामले में पारित प्रकृति के अंतरिम आदेश शिक्षा और इसके कुशल प्रबंधन के लिए हानिकारक हैं। बेशक, इस तरह के अंतरिम आदेश पारित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वे पथभ्रष्टता हैं और यह अकादमिक अनुशासन के विध्वंसक हैं।

पंद्रह. क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई बनाम शीना पक्थम्बरन में, इस न्यायालय ने देखा है: (एससीसी पृष्ठ 724, पैरा 6)

"6 इस न्यायालय ने पहले कई मौकों पर याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के तहत छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की प्रथा की निंदा की है। ऐसे अधिकांश मामलों में अंततः यह दलील दी जाती है कि चूंकि पाठ्यक्रम समाप्त हो गया था या परिणाम घोषित कर दिया गया था, इसलिए मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यह बहुत अजीब और कठिन परिस्थितियों में परिणत होता है। नियम कानूनी प्रावधानों के खिलाफ सहानुभूति और रियायतों की दलील के सामने सीधे घूरते हैं।

सोलह. सीबीएसई और अन्य वी. पी. सुनील कुमार मामले में जिन संस्थानों के छात्रों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा लेने की अनुमति दी गई थी, वे परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं थे।

तहक़ीक़ात। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के तहत उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 381, पैरा 4)

"4.... लेकिन एक गैर-संबद्ध संस्थान के छात्रों को अदालत के आदेशों के तहत बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देना और फिर बोर्ड को परीक्षा देने वालों के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर करना कानून के उल्लंघन के समान होगा और यह न्यायालय छात्रों के पक्ष में गलत सहानुभूति पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों को बनाए रखने के लिए न्यायसंगत नहीं होगा।

सत्रह. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कुमार बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अंतरिम आदेश अकादमिक अनुशासन का उल्लंघन है। प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: (एससीसी पृष्ठ 403, पैरा 7)

"एल .... हमें डर है कि इस तरह के वार्ताकार उपचारों का प्रशासन, सहानुभूति द्वारा निर्देशित अक्सर पूरी तरह से गलत होता है, किसी की कोई सेवा नहीं करता है। अकादमिक मामलों में हमारे सामने आने वाले आदेशों की श्रृंखला से, हम पाते हैं कि ढीली, अकल्पित सहानुभूति निजी परोपकार में पतित होने की आलोचना के लिए न्यायिक विवेक को उजागर करने वाले वार्ताकार न्याय के रूप में मुखौटा लगाती है। यह अकादमिक अनुशासन का विध्वंसक है, या जो कुछ भी बचा है, वह अकादमिक जीवन में गंभीर गतिरोध पैदा करता है। उम्मीदवारों की पात्रता की परवाह किए बिना प्रवेश का आदेश नहीं दिया जा सकता है ... अदालतों को अकादमिक अधिकारियों को उनके कार्यों को अपने हाथों में लेने के लिए शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।

अठ्ठारह. फिर भी एक अन्य मामले में यानी एआर क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में। इस न्यायालय ने कहा कि: (एससीसी पी. 678, पैरा 10)

"हम अपने आदेश से विश्वविद्यालय को उस क़ानून की अवज्ञा करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं जिसके लिए वह अपने अस्तित्व और स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों का श्रेय देता है। हम कानून की अवहेलना करने के लिए अदालत के निर्देश से ज्यादा विनाशकारी कानून के शासन की कल्पना नहीं कर सकते।

उन्नीस. राज्य ओ (तमिलनाडु बनाम सेंट जोसेफ टीचर सी रेनिंग इंस्टीट्यूट) में इस न्यायालय ने कहा कि अनधिकृत शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को प्रवेश देने और परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें दंडित करने के निर्देश को अनुचित माना गया है और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र जो कानूनी रूप से सरकार के शैक्षिक विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और मैं न्यायालय ने ऐसे छात्रों को सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने में त्रुटि की।

बीस. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम निखिल गुलाटी मामले में, इस न्यायालय ने निर्देश जारी करने के लिए आई लीग कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रथा की निंदा की और यह भी कहा कि इस तरह के विपथन को भविष्य में एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

इक्कीस. में कृष्णा प्रिया गांगुली वी। लखनऊ विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट ने देखा: (एससीसी पी. 310, पैरा 3)

"3 जब भी कोई रिट याचिका दायर की जाती है, तो याचिका को स्वीकार किए जाने पर अनंतिम प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि अदालत पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए कि याचिकाकर्ता के पास एक कच्चा लोहा मामला है जो सफल होने के लिए बाध्य है या त्रुटि इतनी सकल या स्पष्ट है कि कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है।

बाईस. महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव राउंडल मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि गैर-मान्यता प्राप्त और अनधिकृत शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका दायर होने पर परीक्षा में बैठने और मान्यता प्राप्त संस्थानों में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पी. 439, पैरा 12)

(एक) .... शिक्षा के तरीके और जांच प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए मानक और न्यायिक आदेश को ढीला करना शिक्षा के कुशल प्रबंधन के लिए हानिकारक है।

(अठ्ठाईस) सभी निष्पक्षता में, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का विज्ञापन करते हुए, यह देखा जा सकता है कि मोनिका रांका के मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

उच्च न्यायालय के निर्णय कि छात्रों का प्रवेश अवैध और अनियमित था और उनकी पढ़ाई को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था, उसमें तथ्यों और परिस्थितियों में, यह माना गया कि एक विशेष मामले के रूप में, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्ति के प्रयोग में था कि अपीलकर्ताओं को अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

(उन्तीस) (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिप्पाथोमस और अन्य बनाम भारतीय आयुवज्ञान परिषद और अन्य मामले में यह निर्णय देते हुए कि भारतीय आयुवज्ञान परिषद के विनियमों का उल्लंघन करते हुए महाविद्यालयों द्वारा अनियमित प्रवेश किए गए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायसंगत राहत प्रदान की क्योंकि उसमें छात्रों ने 414 वर्षों तक अध्ययन जारी रखा

था और मेडिकल कॉलेजों की विवरणिका को सांविधिक राज्य प्रवेश पर्यवेक्षी समिति द्वारा भी अनुमोदित किया गया था।

(तीस) राजन पुरोहित और अन्य बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले 117 छात्रों को एमसीआई विनियमों के विनियम 5 के खंड (2) का उल्लंघन किया गया था, हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उनके प्रवेश में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

(इक्तीस) राजेंद्र प्रसाद माथुर के मामले (सुप्रा) में, छात्रों को कुछ कॉलेजों में प्रवेश दिया गया था और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत चार साल से पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे थे। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी।

(बत्तीस) बीसी चतुर्वेदी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालयों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 142 के समानांतर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे यह सोचने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि उन्हें पूर्ण न्याय नहीं करना है और जहां भी आवश्यक हो, राहत पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए होनी चाहिए, हालांकि यह उतना व्यापक नहीं हो सकता है जितना कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत किया है संविधान।

(तैंतीस) अर्चना के मामले (सुप्रा) में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरह, उच्च न्यायालय भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इक्विटी और निर्णय ले सकता है

समानता के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय यदि किसी विशेष मामले के तथ्यों पर लागू होता है, तो यह एक बाध्यकारी मिसाल बन जाता है।

(चौंतीस) अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे अपने स्वयं के तथ्यों पर असाधारण हैं, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, उन्हें चिकित्सा अध्ययन को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि एमसीआई विनियमों के विनियमन 5 (5) (ii) के तहत आवश्यकता पूरी नहीं होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के दायरे को परिभाषित करते हुए, एबी भास्कर बाओ बनाम पुलिस निरीक्षक, सीबीआई, वाशकपट्टनम (23) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न संविधान पीठ के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार देखा: -

पीठ की ओर से बोलते हुए हममें से एक न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने संविधान पीठ के फैसलों सहित पचास से अधिक फैसलों का उल्लेख किया। प्रासंगिक पैरा, जो उपयोगी है, उद्धृत किया जा सकता है: (मनीष गोयल मामला एससीसी पृष्ठ 398-401, पैरा 11-18)

"11. हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि यह न्यायालय विवाह के विघटन के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जहां न्यायालय पाता है कि विवाह पूरी तरह से अव्यावहारिक है, भावनात्मक रूप से मृत है, बचाव से परे है और असुधार्य रूप से टूट गया है, यहां तक कि मामले के तथ्य भी कानून में ऐसा आधार प्रदान नहीं करते हैं जिस पर तलाक दिया जा सके। तलाक की डिक्री को पार्टियों के बीच सभी मुकदमों को शांत करने और उन्हें और पीड़ा से बचाने के लिए दिया गया है, जैसा कि रोमेश चंदर बनाम सावित्री, कंचन देवी बनाम प्रमोद कुमार मित्तल, अनीता सभरवाल बनाम अनिल सभरवाल, अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन झवेरी, किरण बनाम शरद दत्त, स्वाति वर्मा बनाम राजन वर्मा के निर्णयों से स्पष्ट है। हार्पित सिंह आनंद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जिमी सुदर्शन पुरोहित बनाम सुदर्शन शरद पुरोहित, दुर्गा प्रसन्न त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी, नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली, संघमित्रा घोष बनाम काजल कुमार घोष, ऋषिकेश शन्ना बनाम सरोज शन्ना, समर घोष बनाम जया घोष और सतीश सितोलक बनाम गंगा। हालांकि, ये ऐसे मामले हैं, जहां यह न्यायालय कानून में विधायिका द्वारा प्रदान नहीं किए गए तलाक के आधार पर पार्टियों को बचाने के लिए आया था।

बारह. अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर में, इस न्यायालय ने एक स्थानांतरण याचिका की अनुमति देते हुए संबंधित अदालत को अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की वैधानिक आवश्यकता की अनदेखी करते हुए आपसी सहमति से तलाक के मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। अनिल कुमार जैन मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि वैधानिक आवश्यकताओं को माफ करने का आदेश केवल इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जा सकता है। उक्त शक्ति किसी अन्य न्यायालय में निहित नहीं है।

तेरह. हालांकि, हमने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भी ध्यान दिया है • इस आशय के विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए कि यदि तलाक देने के लिए कानूनी आधार गायब है, तो इस तरह की शक्ति का प्रयोग कानून के समान है और इस प्रकार विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण है, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है (चेतन दास बनाम कमला देवी और विष्णु दत्त शर्मा बनाम मंजू शन्ना के अनुसार)।

चौदह. आम तौर पर, किसी भी अदालत के पास कानून के विपरीत निर्देश जारी करने की क्षमता नहीं है और न ही अदालत वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए किसी प्राधिकरण को निर्देश दे सकती है। अदालतें कानून के शासन को लागू करने के लिए अभिप्रेत हैं और उन आदेशों या निर्देशों को पारित नहीं करती हैं जो कानून द्वारा दिए गए आदेशों के विपरीत हैं। (पंजाब राज्य बनाम रेणुका सिंगला, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र, भारत संघ बनाम किर्लोस्कर न्यूमेटिकको। (ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाम डा आनन्द प्रकाश मिश्रा और कर्णाटक एसआरटीसी बनाम अशरफुल्ला खान) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है।

पंद्रह. . इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयोग में। एआईआर 1963 एससी 996 निम्नानुसार आयोजित किया गया: (एआईआर पी. 1002, पैरा 12)

'12. ... एक आदेश जो यह न्यायालय पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए कर सकता है, न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि यह प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के मूल प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं हो सकता है?

इस न्यायालय की संविधान पीठों ने उच्चतम न्यायालय बार अस्सन, बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के मामले में निर्णय लिया था। भारत संघ और ई.एस.पी. भारत संघ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, यह न्यायालय पूरी तरह से नहीं कर सकता है

किसी संविधि के मूल उपबंधों की उपेक्षा करना और किसी ऐसे मुद्दे से संबंधित आदेश पारित करना जिसे केवल किसी अन्य संविधि में विहित तंत्र के माध्यम से ही निपटाया जा सकता है। इसका प्रयोग आसानी से नहीं किया जाना चाहिए जहां कानून में कोई आधार नहीं है जो एक अधिरचना के निर्माण के लिए एक भवन बना सकता है।

सोलह. इसी तरह के विचार को ए.आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, बोनक्या बनाम में दोहराया गया है। बनाम महाराष्ट्र राज्य, कॉमन कॉज v. भारत संघ, एम.एस.अहलावत वी. हरियाणा राज्य, एमसी मेहता बनाम कमलनाथ, पंजाब राज्य बनाम राजेश स्याल, डब्ल्यूबी सरकार (v) तरुण के. रॉय, टेक्सटाइल लेबरअस्स। v. आधिकारिक परिसमापक, कर्नाटक राज्य बनाम एएमसीसीआरबीआई, भारत संघ वी। शारदिन्दु और भारत सेवा संस्थान बनाम यू.पी. लिमिटेड।

सत्रह. InTcri Oat Estates (P) Ltd. v. UT, Chandigarh इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया: (SCC p. 144, para 36)

छतीस.... आईटीएससीएल द्वारा सहानुभूति या भावना इस संबंध में एक आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है जिसके संबंध में अपीलकर्ता कानूनी अधिकार स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहते हैं। ... भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित एक असाधारण संवैधानिक क्षेत्राधिकार के बावजूद, यह न्यायालय आमतौर पर एक आदेश पारित नहीं करेगा जो एक वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में होगा।

अठ्ठारह. लक्ष्मीदास मोरारजी बनाम बेहरोस्क दरब मदान मामले में, संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधानों से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है: (एससीसी पृष्ठ 433, पैरा 25)

उन्नीस. . ... संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है और इसलिए, वैधानिक अधिनियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जो इस विषय से संबंधित अभिव्यक्त सांविधिक उपबंधों को लागू करने या अभिव्यक्त सांविधिक उपबंधों की अनदेखी करने वाला हो, साथ ही इन संवैधानिक शक्तियों को किसी भी सांविधिक उपबंधों द्वारा किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 1 लोकेवीसीआर। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस शक्ति का उपयोग मामले पर लागू कानून को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। 1 टीआईआईएस का अर्थ है कि अनुच्छेद 142 के तहत कार्य करते हुए, उच्चतम न्यायालय एक आदेश पारित नहीं कर सकता है या राहत प्रदान नहीं कर सकता है जो पूरी तरह से असंगत है जो मूल या वैधानिक के खिलाफ है

यशर सिंह और अन्य यू स्टेट ओई हरियाणा और 01'1 आईई आरएस (अजय कुमार मित्तल, जे। मामले से संबंधित अधिनियमन। इली पावर का उपयोग आसानी से किया जाना है जिसे कानून के मौजूदा समर्थक दृष्टिकोण द्वारा प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निपटा नहीं जा सकता है या जब कानून के प्रावधान पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय नहीं ला सकते हैं।

(35) यद्यपि 20.12.2012 को अपील की सुनवाई करने वाली प्रस्ताव पीठ ने अपीलकर्ताओं को कक्षाओं में भाग लेने और परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी, जो विशेष रूप से इस शर्त के साथ थी कि यह कानून में किसी भी अधिकार या उनके पक्ष में इक्विटी को रद्द नहीं करेगा, रिट याचिका में भी इसी तरह का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इक्विटी या कानून में किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। एमसीआई विनियमों के विपरीत अपने प्रॉस्पेक्टस को प्रकाशित करने में फ्लिक कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा की गई गलती से छात्र को प्रवेश के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा

जो कानून की अदालत में लागू करने में सक्षम होगा। साथ ही, छात्रों के लिए कानून के अनुसार गलत करने वाले के खिलाफ उपयुक्त नुकसान का दावा करने के लिए खुला होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुवळ्ाना परिषद इस मामले की भी जांच करेगी और ऐसी त्रुटि, जिसने अपीलकर्ताओं के कैरियर को प्रभावित किया है, के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय के विरुद्ध उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगी। 36. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, उसी चाप को खारिज कर दिया गया।

A. जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा